राष्ट्रपति के 2020 के अभिभाषण के मुख्य अंश

भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने 31 जनवरी, 2020 को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। उन्होंने अपने अभिभाषण में सरकार की प्रमुख नीतिगत उपलब्धियों को रेखांकित किया। अभिभाषण के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं:

अर्थव्यवस्था

- सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर का बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 450 बिलियन USD से भी अधिक का है। अप्रैल से अक्टूबर 2019 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तीन अरब USD बढ़ा है।
- ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत 2014 में 142वें स्थान पर था, 2020 में यह 63वें स्थान पर है। कॉरपोरेट टैक्स में कटौती और श्रम कानूनों के संहिताबद्ध होने से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में और सुधार होगा।

वित्त और बैंकिंग

- इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता, 2016 की वजह से बैंकों और अन्य संस्थानों के करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए वापस आए हैं।
- विलय से लघु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सशक्त हुए हैं और उनकी ऋण क्षमता में सुधार हुआ है। 2019-20 की पहली छमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लाभ कमाया है।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत 450 योजनाओं की राशि को लाभार्थियों के खातों में सीधे जमा किया गया है। 2014 से डीबीटी के जरिए नौ लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त डीबीटी ने 1.7 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से रोका है।
- देश में 121 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है तथा लगभग 60 करोड़ लोगों के पास रूपे कार्ड हैं। 38 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं।
- संसद ने गरीबों की बचत की रक्षा करने के लिए अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, 2019 और गरीबों को चिट फंड योजनाओं के धोखे से बचाने के लिए चिट फंड्स संशोधन एक्ट, 2019 पारित किया है।

आंतरिक मामले और रक्षा

- कुछ प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए संसद ने नागरिकता संशोधन एक्ट, 2019 को पारित किया है।
- जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को रद्द किया गया है।
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति और सैन्य मामलों के विभाग की स्थापना से तीनों सेनाओं के बीच समन्वय में सुधार होगा और उनके आधुनिकीकरण के काम में तेजी आएगी।
- जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों का दायरा निरंतर सिमट रहा है।

कृषि

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 43,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आठ करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में जमा हुई है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 5.5 करोड़ से अधिक किसानों ने बहुत कम प्रीमियम पर अपनी फसलों का बीमा कराया है। पिछले तीन वर्षों में योजना के अंतर्गत 57,000 करोड़ रुपए मूल्य के दावों का निपटान किया गया है।
- खरीफ और रबी की फसलों के लिए एमएसपी में लगातार वृद्धि हुई है। दलहन और तिलहन की खरीद में 20 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

प्राची कौर
prachi@prsindia.org

31 जनवरी, 2020

- मछुआरों की आय और मछली का उत्पादन, दोनों को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ फिशरीज़ विभाग की स्थापना की गई है।

मैन्यूफैक्चरिंग और रोजगार सृजन

- देश में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का मूल्य 2014-15 में 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2018-19 मे 4.6 लाख करोड़ रुपए हो गया।
- विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टम भारत में है। स्टार्ट अप इंडिया अभियान के अंतर्गत देश में 27,000 नए स्टार्ट अप्स को मान्यता दी जा चुकी है।
- मुद्रा योजना के अंतर्गत देश में 5.5 करोड़ से ज्यादा नए उद्यमियों ने ऋण लिया है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण दिया जा चुका है।
- 2014 में देश के ग्रामीण इलाकों में 60,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स थे, जो 2019 में बढ़कर 3.65 लाख हो गए हैं। इससे 12 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को रोजगार मिला है।

शहरी और ग्रामीण विकास

- सरकार आने वाले वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 25 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी।
-

श के 112 जिलों में विकास के अनेक मापदंडों में प्रभावी सुधार हुआ है और कई जिले अब अपने राज्य के औसत के बराबर आ चुके हैं।

- सरकार ने घर बनाने के लंबित प्रॉजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए की राशि दी है।
- दो करोड़ गरीब लोगों को घर दिए गए हैं।

परिवहन

- अगले पांच वर्षों में परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 1,25,000 किलोमीटर सड़कें बनाई और अपग्रेड की जाएंगी।
- मोटर वाहन संशोधन एक्ट, 2019 पारित किया गया है जिसका लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है।
- देश के 18 शहरों में मेट्रो की सुविधा का विस्तार किया गया है और 670 किलोमीटर की मेट्रो लाइनों को पारिचालित किया जा रहा है।

ऊर्जा

- देश में पेट्रोलियम गैस कवरेज 55% से बढ़कर लगभग 97% हो गया है। आठ करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन और 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया गया है।
- रीन्यूएबल एनर्जी उत्पादन के लक्ष्य बढ़ाकर 450 गिगावॉट कर दिया गया है।

शिक्षा

- 75 शिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी के जरिए 37,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की गई है।
- सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में 7,000 शिक्षकों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहल की है।

स्वास्थ्य

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 75 लाख गरीबों को मुफ्त उपचार की सुविधा मिली है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 27,000 से अधिक स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों की स्थापना की दे गई है।
- 1,000 से अधिक जरूरी दवाइयों की कीमतें नियंत्रित करने से मरीजों को 12,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है।
- 50 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपए तक की मुफ्त उपचार सुविधा और 24 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज मिला है।
- 2019 में 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाने को स्वीकृति दी गई है जिससे देश में लगभग 16,000 एमबीबीएस और 4,000 से अधिक पोस्ट ग्रैजुएशन सीटों की बढ़ोतरी होगी।

महिला और बाल विकास

- 6.6 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों में शामिल हुईं। इन महिलाओं को निम्न ब्याज दरों पर ऋण दिए गए हैं।
- महिला सुरक्षा की दृष्टि से देश में 600 से अधिक वन स्टॉप सेंटर, 1,000 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क बनाए गए हैं।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 12 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं।
- मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए तीन तलाक विरोधी कानून और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की सजा सख्त करने वाला कानून पारित किया गया।

अल्पसंख्यक और आदिवासी मामले

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा और विधानसभा में मिलने वाला आरक्षण अगले दस वर्षों के लिए बढ़ाया गया।
- दिव्यांग जनों के लिए आरक्षण और कानूनी सशक्तीकरण में बढ़ोतरी हुई है। पिछले पांच वर्षों में उन्हें 900 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत वाले उपकरण उपलब्ध कराए गए।
- सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए वन उत्पादों पर एमएसपी का लाभ दिया है। सरकार द्वारा देश में 400 से ज्यादा एकलव्य मॉडल रेज़िडेंशियल स्कूल खोलने का अभियान शुरू किया गया है।

जल और पर्यावरण

- देश के गांवों में हर घर तक पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेय जल पहुंचे, इसके लिए सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है। इस योजना पर 3,60,000 रुपए खर्च किए जाएंगे।
- नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 7,24,00 करोड़ रुपए के प्रॉजेक्ट्स पर काम पूरा हो चुका है।
- वायु प्रदूषण से निपटने के लिए देश के 102 शहरों में नेशनल क्लीन एयर कार्यक्रम लागू किया जा रहा है।
- 2015 से वृक्ष और वन क्षेत्र 13,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक बढ़ा है।

अंतरिक्ष में खोज और प्रौद्योगिकी

- सरकार ने चंद्रयान-3 को स्वीकृति दी है। इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम- गगनयान तथा आदित्य-एक मिशन पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है।
- डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग के बीच डेटा प्राइवेसी के संरक्षण हेतु सरकार ने संसद में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 को पेश किया है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।